



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 76] नई दिल्ली, बुधवार, जून 6, 1984/ज्येष्ठ 16, 1906
No. 76] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 6, 1984/JYAISTHA 16, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असल संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 31-आई०टी-सी० (पीएन)/84

नई दिल्ली, 6 जून, 1984

विषय : 1982-83 के लिये जापान सरकार द्वारा प्रदत्त येन
1,948 बिलियन (येन 1,948,670,000/-) (ऋण
सहायता) की जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत
सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों के संबंध में लाइसेंस शर्तें।

मि० सं० आई० पी० सी/23(2)/84—1982-83
के लिये जापान सरकार द्वारा प्रदत्त येन 1,948 बिलियन
(ऋण सहायता) की जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत
सार्वजनिक क्षेत्र के, आयातों के संबंध में लाइसेंस के लिए
लागू होने वाली जैसी शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के
परिशिष्ट में दी गई हैं वे जानकारी के लिये अधिसूचित की
जाती हैं।

प्रकाश चन्द्र जैन, मुख्यनियंत्रक, आयात-निर्यात

सार्वजनिक सूचना संख्या 31-आई टी सी (पी एन)/84
दिनांक : 6 जून 1984 वाणिज्य मंत्रालय का परिशिष्ट

जापान की सरकार द्वारा प्रदान किये गये 1982-83
के लिये येन 1,948 बिलियन (येन 1,948,670,000 रु०)
(ऋण सहायता) की जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत
सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों के संबंध में लाइसेंस शर्तें।

खण्ड-1—सामान्य शर्तें

1(1) जापान की सरकार द्वारा प्रदान की गई येन
1,948 बिलियन जापानी अनुदान सहायता भारत के अलावा
अं० ई० सी० डी० और विकासशील देशों के दृक में संगठित
की गई है। तदनुसार इस ऋण के अधीन अधिप्राप्त की
जाने वाली पण्य वस्तुओं और उनमें संबंधित प्रासंगिक सेवायें
जापान और अनुबंध-1 की सूची में उद्धृत सभी देशों से
आयात की जा सकती हैं। वे देश इस अनुदान के अंतर्गत
पात्र स्त्रात देश होंगे। इस अनुदान सहायता के अधीन जो
पात्र मर्दे आयात की जा सकती हैं उनकी सूची अनुबंध-2
में दी गई है।

1(2) लाइसेंस पर एक शीर्षक "1982-83 के लिये येन 1,948 बिलियन जापानी अनुदान सहायता" होगा। प्रथम और द्वितीय प्रत्यक्ष के लिये लाइसेंस संकेत "एस/जे० एन" होगा। ये प्रत्यक्ष मुद्रा निर्यातक आयात-निर्यात के लिये आयात लाइसेंस के अग्रेषित पत्र में भी दुहराये जायेंगे।

1(3) बैंक खर्च जिनका प्रेषण सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के किसी भी प्रेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जायेगी। भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान अभिकर्ता को भारतीय रुपये में चुकाना चाहिये। लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिये लाइसेंस पर ही प्रभावित किये जायेंगे।

1(4) आयात लाइसेंस लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर 12 महीनों को प्रारंभिक वर्ष अवधि के साथ जारी किया जायेगा। लाइसेंस की वैधता में वृद्धि के लिये लाइसेंसधारी को संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिये जो इस मामले में आधिकार्य विभाग (जापान अनुभाग) से परामर्श करेगा।

1(5) पक्के आदेश अनुबंध-1 में उल्लिखित जापान या अन्य पात्र देशों में स्थित विदेशी संभरकों को लागत और भाड़ा के आधार पर दिये जाने चाहिये और वे (आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीने की अवधि के भीतर) अवर सचिव (टी ए) आधिकार्य विभाग (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेज दिये जाने चाहिये। "पक्के आदेशों" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा दिये गये उन क्रय आदेशों का क्रय संविदाओं से है जो भारतीय लाइसेंसधारी से प्राप्त आदेश की पुष्टि करने के बाद विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् समर्थित हों या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हों। विदेशी संभरकों को भारतीय अभिकर्ताओं के आदेश और/या भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकार्य नहीं है।

1(6) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जायेगा जब तक कि ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय आधिकार्य विभाग, जापान अनुभाग को नहीं पहुंच जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1(5) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर बंध कारणों से नहीं दिये जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश क्यों नहीं दिये जा सके इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिये ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जायेगा। वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिये वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 4 महीनों से अधिक

के लिये मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आधिकार्य विभाग (जापान अनुभाग) नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजे जायेंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिये प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसे वे लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे।

पोत-लदान के लिये आखिरी तिथि निर्दिष्ट करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि यह तिथि 31-3-1986 के बाद की न हो।

खण्ड-2—संभरण ठेके का समझौता करने समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें

2(1)(क) ठेके का लागत और भाड़ा मूल्य येन या यू० एस० डालर या पौण्ड स्टर्लिंग में एक येन, एक सेंट या एक पैसे से कम की भिन्न के बिना ही अभिव्यक्त होना चाहिये। और इसमें भारतीय अभिकर्ता का कमीशन यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिये जो कि भारतीय रुपये में चुकाना चाहिये। भारतीय रुपये या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिये। जहाज पर्यन्त निःशुल्क लागत-बीमा और भाड़ा धनराशि अलग-अलग प्रदर्शित की जा सकती है परन्तु ठेके में यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिये कि भाड़े का खर्चा वास्तविक आधार पर देय होगा या ठेके में निर्दिष्ट किये गये भाड़े का खर्च वास्तविक खर्चों के अतिरिक्त देय धनराशि होगी।

(ख) संविदा में नकद आधार पर अर्पित बैंक आफ इंडिया टोकियो को जापानी संभरकों द्वारा पोतलदान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिये।

(ग) क्रय आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश केवल अंग्रेजी में होने चाहिये।

2(2) आयात लाइसेंस के विपरीत केवल एक संविदा की जानी चाहिये। विशेष मामलों में एक से अधिक संविदा की प्रविष्टि की अनुमति दी जा सकती है जिनके लिये वित्त मंत्रालय, आधिकार्य विभाग से आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के तत्काल बाद पूर्व अनुमोदन ले लेना चाहिये।

2(3) संभरक की पात्रता :

संभरक पात्र स्वतंत्र देशों का राष्ट्रिक होगा या पात्र स्वतंत्र देशों में पंजीकृत और समाविष्ट न्यायिक व्यक्ति होगा।

खण्ड-3—संभरक ठेकों में निम्नलिखित शर्त विशेष रूप से समाविष्ट होनी चाहिये :—

3(1) 1982-83 के लिये येन 1,948 बिलियन के अनुदान सहायता से संबद्ध इस संविदा की व्यवस्था 23-2-84 को भारत और जापान की सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार दी गई है।

3(2) विदेशी संभरकों को भुगतान उस "भुगतान के लिये प्राधिकार-पत्र" (ए/पी) के माध्यम से किया जायेगा जो 1982-83 के लिये जापानी अनुदान सहायता के अधीन

बैंक आफ इण्डिया, टोकियो के नाम में सहायता एवं लेखा परीक्षानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किया जायेगा।

3(3) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिये सहमत होगा जो एक और भारत सरकार द्वारा और दूसरी और जापान सरकार द्वारा अपेक्षित हो।

3(4) उस मामले में, जिसमें संभरक जापान में स्थित हो और भारतीय दूतावास टोकियो के परामर्श से पोतलदान की व्यवस्था करने को तैयार है और उसके लिये संबंधित माल की भुगदगी के कार्यक्रम की भारतीय दूतावास टोकियो को सूचना देगा और अपेक्षित पोत परिवहन के लिये कम से कम 6 मन्ताह से पहले ही भारतीय दूतावास टोकियो को अधिसूचित करवायेगा जिससे उचित व्यवस्था की जाये। विशेष मामलों में जहां भारतीय, आयातक यह चाहता है तो अधिसूचना की अवधि कम की जा सकती है। आवश्यक न्योरे देते हुए प्रत्येक पोतलदान के बाद जापानी संभरक को आयातक को केवल सूचना भेजने के लिये भी सहमत होना चाहिये और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजी जानी चाहिये।

खण्ड-4—भारत सरकार द्वारा ठेके का अनुमोदन

4(1) जैसे ही आदेशों की अंतिम रूप दे दिए जाते हैं, लाइसेंसधारी को दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां या समुद्र पास संभरकों को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए क्रय आदेश के साथ समुद्र-पार संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश की चार प्रतियां या उनकी सभी प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियों के साथ अनुबन्ध-3 के प्रपत्र में "ए/पी जारी करने के आवेदन" की दो प्रतियों सहित संगत बैंध आयात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियां अवर सचिव (टी० ए०), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए। उपर्युक्त प्रक्रिया संविदा की विषय-वस्तु या उसकी कीमत के आवश्यक आशोधनों से उत्पन्न सभी संविदा संशोधनों के लिए भी लागू होंगी।

4(2) यदि ठेके के दस्तावेज "ए/पी जारी करने के लिए आवेदनपत्र" और अन्य संबंधित दस्तावेज सही पाए जाएं तो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ठेके का अनुमोदन करेगा और उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेज के एक सेट को, सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक और भारत के राजदूतावास, टोकियो और भारत में जापान के राजदूतावास को भेजने की व्यवस्था करेगा।

4(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित दस्तावेज की प्राप्ति के बाद सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 बैंक आफ इण्डिया, टोकियो के लिए अनुबन्ध-4 के रूप में

विदेशी संभरकों को भुगतान करने के लिए "भुगतान के लिए प्राधिकारपत्र-(ए/पी)" जारी करेगा। ए/पी की प्रतियां भारत के राजदूतावास, टोकियो आयातक, भारत में आयातक के बैंक और जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाएंगी।

4(4) भुगतान के लिए प्राधिकारपत्र (ए/पी) की प्राप्ति के बाद बैंक आफ इण्डिया, टोकियो जापान की सरकार भारत के राजदूतावास, टोकियो, आयातक के भारत में बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को सूचना देते हुए इस प्राप्ति की सूचना से संभरक को अद्विगत कराएगा।

4(5) पोत-लदान प्रभावी करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकों के माध्यम से ए/पी में उल्लिखित दस्तावेज बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इण्डिया, टोकियो दस्तावेज में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरक को उसके बैंकों के माध्यम से रिहा करेगा।

4(6) संभरक के लिए ए/पी जारी करने के लिए और भुगतान की व्यवस्था करने के लिए बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को देय बैंक खर्च, भारत में आयातक के संबद्ध बैंक द्वारा बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को प्रेषण द्वारा सामान्य बैंक प्रणाली से भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना ही निर्धारित किए जाएंगे।

खण्ड-5—रुपया जमा करने का उत्तरदायित्व

5(1) मूल विनियम पोत परिवहन दस्तावेज निरपवाद रूप से बैंक आफ इण्डिया, टोकियो द्वारा भारत में आयातक के संबद्ध बैंक को भेजे जाएंगे जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (जो अनुबन्ध-3 में उल्लिखित हैं) की शाखा होगी उस बैंक को दस्तावेजों के ये विनियम सेट केवल इस बात का सुनिश्चय कर लेने के बाद ही संबद्ध आयातक को देने चाहिए कि विदेशी संभरक को चुकाई गई येन/यू०एस० डालर/पौंड स्टलिंग धनराशि के बराबर रुपया उन मामलों में जहां देने योग्य है ब्याज के खर्च सहित संभरक को भुगतान कर दिया है और उस धनराशि पर विदेशी संभरक को बैंक आफ इण्डिया, टोकियो द्वारा भुगतान की तिथि से वास्तविक रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से और जेप अवधि के लिए 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से हिसाब लगाकर ब्याज सार्वजनिक सूचना सं० 31-आई टी सी (पी एन)/83, दिनांक 10-8-83 के अनुसार सरकारी लेखा में जमा कर दिया गया है। ब्याज दोनों दिनों, अर्थात् जिस दिन विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा किया जाता है के लिए देय है। देखिए सार्वजनिक सूचना सं० 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 74-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-1974 भुगतानों की येन/यू० एस० डालर/पौंड धनराशि के बराबर रुपये की गणना करने के लिए अपनायी

जाने वाला विनिमय दर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं० 8-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 में निर्धारित मुद्रा विनिमय की मिश्रित दर होगी या वह दर होगी जो कि मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए। इस संबंध में कोई भी परिवर्तन जब और जैसे ही आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा। इस बात का सुनिश्चय करने का उत्तर-दायित्व संबद्ध भारतीय बैंक का होगा कि आयात दस्तावेज आयातकों को सौंपने से पहले ही देय धनराशि सरकारी लेखे में सही रूप से जमा कर दी गई है। लाइसेंसधारी को भी यह सुनिश्चय कर देना चाहिए कि असाधारण परिस्थितियों में सीमाशुल्क प्राधिकारियों से माल का वितरण प्राप्त करने पर धनराशि सरकारी लेखे में शीघ्र ही जमा करा दी गई है। जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया जमा कराना चाहिए वह “के डिपोजिट्स एंड एडवान्स-843-सिविल डिपोजिट्स-डिपोजिट्स फ़ोर परचेसिंग एटकेट्स एंड एक्साइज परचेस ग्रान्ट ऐंड फ़्राम गवर्नमेंट आफ़ जापान” फ़ार 1982-83 (येन 1,948 बिलियन) ग्रान्ट ऐंड-ऋण सहायता।

5(2) उल्लिखित धनराशि चालान के दाहिने ओर कोड सं० 5130000009 दर्शाते हुए या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ़ इण्डिया, तीस हजारी, दिल्ली में सरकार की साख में नक़द जमा होगी चाहिए या यदि वह सुविधाजनक न हो तो स्टेट बैंक आफ़ इण्डिया की किसी शाखा या इसके उप-संगी किसी भी राष्ट्रीय-कृत बैंक (हुण्डीकर्तार) से प्राप्त एक हुण्डी (डिमाण्ड ड्राफ़्ट) के माध्यम से स्टेट बैंक आफ़ इण्डिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (हुण्डी ग्राहक और प्रापक) की सार्वजनिक सूचना सं० 184-आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 30-8-1968 सं० 233-आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 24-10-68, सं० 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71, सं० 74-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं० 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित सरकारी लेखे में जमा करने के लिए धनप्रेषण करना चाहिए।

5(3) सरकार द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर सम्बद्ध भारतीय बैंक को ऊपर निर्धारित तरीके से वह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित्त भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगे जाए। चालान के विभिन्न कालों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं० 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 के साथ पढ़ी जाने वाले सार्वजनिक सूचना सं० 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71 के पैरा 2 में निर्धारित सूचना और सार्वजनिक सूचना सं० 74-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-1974 में भी निर्धारित सूचना चालान के कालम “धन प्रेषण और प्राधिकारी (यदि कोई

हो) के पूर्ण ध्यौरे” में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं। खजाना चालान में निम्नलिखित ध्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए :—

- (क) वित्त मंत्रालय के भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र सं० और विनांक।
- (ख) येन मुद्रा को वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाने हैं।
- (ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि।
- (घ) चुकाए गए ब्याज की धनराशि और वह अवधि जिसके लिए यह गिना जाएगा।
- (ङ) जमा की गई कुल धनराशि।

(ब्याज की गणना विदेशी संभरक को भुगतान की तिथि से सरकारी लेखे में समतुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए की जानी है)।

उसके पश्चात् सी० ए० ए० एंड ए० द्वारा जारी किए गए भुगतान के लिए प्राधिकारपत्र का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना चालान रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी० ए० ए० एंड ए० को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी : भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि रुपए का निक्षेप बैंक आफ़ इंडिया, टोकियो से अदायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोतलदान दस्तावेजों की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी० ए० ए० एंड ए०, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

5(4) भारत में संबद्ध बैंक आफ़ इंडिया को लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रक प्रति रुपया निवेशों को धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित “एस” प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया, नई दिल्ली को भेजना चाहिए।

खण्ड-6—विविध शर्तें

6(1) आयात लाइसेंस के उपयोग की रिपोर्ट :— भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र जारी होने के बाद आयातक को पोत लदानों और उनके अधीन किए गए भुगतानों के संबंध में और जो पोतलदान होने वाली हैं, उनके विषय में एक मासिक रिपोर्ट सी० ए० ए० एंड ए०, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

6(2) संभरकों को विशेष शर्तें अधिसूचित करना :— लाइसेंसधारी को चाहिए कि ये आयात लाइसेंस को उन विशेष शर्तों से संभरक को अवगत कराये जो समझौते का पालन करने में संभरकों पर प्रभाव डाल सकती हैं।

6(3) विवाद :—यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो

उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। बैंक आफ इण्डिया, टोकियो द्वारा भुगतानों से पूर्व संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें साफ-2 "भुगतान के नियम" के अधीन अनुबंध-1 में दर्शाई जानी चाहिए। विवादों से निपटने की शर्तें ठेके की शर्तों में शामिल होनी चाहिए।

6(4) भविष्य अनुबंध :—आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों में संबंधित जापान से 1982-83 के लिए अनुदान सहायता के अधीन सभी आभारों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-2 पर जारी किए गए निदेशों या अनुदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरंत पालन करना होगा।

6(5) अतिक्रमण या उल्लंघन :—उपर्युक्त खंडों में स्थिर की गयी शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रक) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

6(6) अनुबंधों की सूची :— अनुबंध-1 पात्र स्त्रोत देशों की सूची

अनुबंध-2 पात्र पण्य वस्तुओं की सूची

अनुबंध-3 भुगतान के लिए प्राधिकारपत्र जारी करने के लिए आवेदन करने का प्रपत्र

अनुबंध-4 भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) का प्रपत्र।

अनुबंध 1

पात्र स्त्रोत देशों की सूची

(क) ओ ई सी डी देश

ऑस्ट्रेलिया
बेलजियम
कनाडा
डेनमार्क
फ़िनलैंड
फ्रान्स
जर्मनी संघीय गणराज्य
यूनान
आइसलैंड आयरलैंड
इटली
जापान
लगजमबर्ग
दो नीदरलैंड
न्यूजीलैंड
नार्वे
पुर्तगाल
स्पेन
स्वीडन
स्वीट्जरलैंड
तुर्की

दि यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स

(ख) विकासशील देश तथा उसके क्षेत्र

(ख 1) नान-ओ०पी०ई०सी०, विकासशील देश

1. अफ्रीका, उत्तरी सहारा

मिश्र
मोरक्को
तुनीशिया

2. अफ्रीका, दक्षिणी सहारा

अंगोला
बोत्सवाना
बुरुंडी
केमेरून
केप वर्डी द्वीप समूह
केन्द्रीय अफ्रीकन गणतंत्र
चाद
कमोरो द्वीप समूह
इथोपिया
गाबिया
कांगो, दक्षिणी गणराज्य (1)
इक्वेटोरियल गार्ईना
घाना
गिनी
आइवरी कोस्ट
कीनिया
लेसोथो
लाइबीरिया
मालागासी गणतंत्र
मलावी
मॉरितानिया
मारीशस
मोजम्बीक
नाइजर
पुर्तगाल गिनी
रि-यूनियन
रोडेसिया
रवाण्डा
सेंट हेलेना और डेप (2)
सो टोम प्रिन्सीपि
सेनेगाल
सिचिलीज
सियरा लिओन
सोमालिया
सूडान
स्वाजीलैंड
टेरों अफार्स और इस्तास (3)

टोगों	पोरू
युगान्डा	सूरिनाम
तंजानिया गणतंत्र संघ	उरुग्वे
अपर वोल्टा	5. मध्य पूर्वी एशिया
जायरे गणतंत्र	बेहरीन
जाम्बिया	इजराइल
3. अमेरिका-उत्तरी और केन्द्रीय	जोर्डन
बेल्जियम	लेबनान
बारबाडोस	ओमान
ब्रिटेन	सिरियाई अरब गणतंत्र
बरमुडा	यूनाइटेड अरब एमिरात
कोस्टारिका	यमन अरब गणतंत्र (3)
क्यूबा	यमन जनवादी डी० आर० (4)
डोमिनिकन गणतंत्र	6. दक्षिणी एशिया
एल साल्वाडोर	अफगानिस्तान
गुवाटेलायुप	बांग्ला देश
ग्वाटेमाला	भूटान
हैती	बर्मा
होन्डुरस	मालदीव
जैमेका	नेपाल
मार्टिनिक	पाकिस्तान
मैक्सिको	श्रीलंका
नीदरलैंड एनाटिलीज	7. सुदूर पूर्व एशिया
निकारागुआ	बुर्नेई
पनामा	हांगकांग
सेन्ट पियरी और मिल्कूलोन	खेमेर गणतंत्र
ट्रिनिडाड और टोबागो	कोरिया गणतंत्र
अमेरिका उत्तरी और केन्द्रीय (क्रमशः)	साओस
वेस्ट इण्डीज (शाखा) एन०आई०ई०,	मकाओ
(क) संबंधित राज्य (1)	मलेशिया
(ख) आश्रित राज्य (2)	फिलीपाइन
4. दक्षिणी अमेरिका	सिंगापुर
अर्जेंटीना	ताइवान
बोलिविया	थाईलैण्ड
ब्राजील	तिमोर
चिली	बियतनाम गणतंत्र
कोलम्बिया	बियतनाम जनवादी गणतंत्र
फाल्कलैंड द्वीप समूह	8. ओसिनिया
फ्रांसिमी गिनी	कोक द्वीप
गुयाना	समूह
पाराग्वे	किनी
	गिल गिल्बर्ट और इलाइस द्वीप
(1) पहले स्पेनी गिनी का प्रवेशफरनेडो द्वीप समूह ।	फ्रांसिमी पोलिनेशिया (5)
(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित : असेन्शन, ट्रिस्टन डा इन	नौरू
एक्सेसिवस, नाइटिंगेल, गफ ।	न्यूकोलेडोनिया
(3) ऐन समूह, अरबा, बोनाहूरे, क्यराकाओ सहा, सेंट	न्यूकेप्रिसेस (ब्रि० और फ०)
युस्टासिट, सेंट मारटिन (दक्षिण भाग)	हिडू
	पैसिफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य) (6)

पापुआ न्यू गिनी
सोलापन द्वीप समूह (हि)
टोंगो
वालिस और फुतुना
पश्चिम समाओ

9. यूरोप

साइप्रस
जिब्राल्टर
ग्रीक
माल्टा
स्पेन
तुर्की
युगोस्लाविया

(खण्ड-2) ओ०पी०ई०सी० के सदस्य या सहयोगी देश :

अल्जीरिया	सऊदी अरब
बोलिविया	आबू धाबी
नीबियार्ह अरब गणतंत्र	इन्डोनेशिया
गेवान	
नाइजीरिया	
इक्वेडोर	
वेन्युएला	
ईरान	
ईराक	
कुवैत	
कातार	

अनुबंध 2

पात्र पण्य सूची

1. रोज़
 2. विशेष इस्पात और मिश्र-धातु इस्पात सहित इस्पात
 3. टूकों और ट्रैक्टरों के विनिर्माण के लिए संघटक, संयोजक और पुर्जे।
-
- (1) मुख्य द्वीप एन्टिगुवा, डोमिनिका, ग्रेनेडा, सेंट किट्स (सेन्ट क्रिस्टोफ़े), नेविस ग्रंगुइला, सेंट लूसिया और सेंट विसेन्ट।
 - (2) मेन आई लैंड, मोन्तेसे रेंड, गेमान, तुर्की और काइकोस और ब्रिटिश वरजिन द्वीप समूह।
 - (3) अजमन, दुबई, फजाइरह, रास अल खेमाह शेरजाह और उम्मल क्वैयन।
 - (4) अदन और विभिन्न सल्तनत और अमीरात सहित।
 - (5) सोसायटी आईलैंड्स समूह (ताहिती सहित) को शामिल करते हुए आस्ट्रेल द्वीप समूह, टुआमोट, जांबियर ग्रुप और मार्केसल द्वीप समूह।
 - (6) पैसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रवेश, कारोलीन द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह और पेरीना द्वीप समूह (गाम को छोड़कर)

4. रसायन

5. जापान अनुदान परियोजना और भारत-जापान संयुक्त उद्यम के लिए फालतू पुर्जे, संघटक और कच्चा माल।
6. बिजली के हलों के लिए संघटक, संयोजक और फालतू पुर्जे।
7. मशीनरी, संघटक, संयोजक, फालतू पुर्जे और कच्चा माल
8. लघु उद्योग क्षेत्र के लिए मशीनरी और उपस्कर
9. तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र के लिए मशीनरी, उपस्कर और फालतू पुर्जे।
10. उर्वरक और ऐसी अन्य मर्चे, जिन पर आपस में सहमति हो।

अनुबन्ध-3

“भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना-पत्र”
सं० दिनांक

सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग,
प्रथम मंजिल,
पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली-110001

विषय : 1982-83 के लिए येन 1,948 बिलियन जापानी
ऋण अनुदान सहायता येन के अधीन जापान से आयात।
महोदय,

अपर उल्लिखित अनुदान सहायता के अधीन जापान से जो कि आयात के संबंध में है संबद्ध संस्करण के नाम में बैंक आफ इंडिया, टोकियो के लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आपको निम्नलिखित ध्याये प्रस्तुत करते हैं :—

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता

(ख) आयात लाइसेंस की सं०, दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक वैध है।

(ग) प्राप्ति के तरीके—क्या यह सीधे क्रय या औपचारिक खुले अंतर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है। इसके मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतिक होना चाहिए कि क्या निविदा का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण

(ङ) माल का उद्गम देश

(च) निविदा का कुल लागत भाड़ा मूल्य (येन में)

- (छ) यदि कोई हो तो, भारतीय रुपए में भुगतान की जाने वाली भारतीय एजेंट के कमीशन की धन-राशि।
- (ज) वह कुल लागत तथा भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता है।
- (झ) संभरकों के साथ की गयी संविदा की संख्या और दिनांक।
- (ञ) संभरक का नाम और पता।
- (ट) वे भुगतान शर्तें और संभावित तिथि जिनको संविदा के अंतर्गत भुगतान देय होंगे।
- (ठ) मुपुर्दगी की पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि।
- (ड) भारतीय बैंक टोकियो को भुगतान करते समय किए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और निपटान का संकेत करें) प्रत्येक सेटों की संख्या और उनका निपटान दिखाने हुए।
- (ढ) पोत-लदान अनुदेश (वाहनान्तरण/पार्टे-शिपमेंट की अनुमति दी गई है या नहीं निर्दिष्ट कीजिए)।
- (ण) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता।
- (त) क्या उसी लाइसेंस के अंतर्गत संविदा (संविदाओं) कर दी गई हैं। यदि हां, तो ऐसी संविदा को दिनांक और मूल्य।

भवदीय

अनुबन्ध-

संख्या

भारत सरकार,

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग,

नई दिल्ली,

दिनांक

सेवा में,

बैंक आफ इंडिया,

टोकियो शाखा,

टोकियो (जापान)

विषय : येन 1,948 बिलियन के लिए जापान ऋण अनुदान सहायता के अन्तर्गत आयात भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

1. आपके बैंक के साथ 13-3-79 को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद् द्वारा यथा संलग्न ध्यारे (जो परिशिष्ट में दर्शाए गए हैं) के अनुसार सर्वश्री

के नाम में येन धनराशि के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

2. कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की पावती के बारे में संभरकों को सूचना दें और इसकी प्रत्येक सूचना पत्र की एक प्रति जापान सरकार आयातक-बैंक, भारत के राज-दूतावास, टोकियो और इस मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाए।

3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान परिशिष्ट में यथा संकेतित लदान दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

4. आयातक द्वारा आपको दस्तावेज को भेजने आदि के लिए भाड़ों सहित अदा किए जाने वाले बैंकिंग भाड़े टोकियो में भारतीय दूतावास/आयातक के बैंक द्वारा निर्धारित किए जायेंगे।

5. जैसे ही संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए लदान दस्तावेज के आधार पर आपके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में मंत्रालय और आयातक के बैंक को भेजी जानी चाहिए।

6. इस मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता है।

7. यह भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र तक वैध रहेगा।

भवदीय,

लेखा अधिकारी।

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :—

1. आयातक को उनके पत्र सं० दिनांक के संदर्भ में।

2. आयातक का बैंक उनसे निवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंक आफ इंडिया, टोकियो आंच से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरकों को येन/यू०एस० डालर/पौण्ड के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें। विदेशी संभरकों को खुफाई गई धनराशि के बराबर रुपए की गणना सार्वजनिक सूचना सं० 8-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए, के अनुसार विदेशी संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि से सरकार के लेखे में तुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना सं० 46-आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 16-6-76 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 12 प्रतिशत वार्षिक दर पर और इससे अधिक की गणना की गई

अवधि के लिए 18 प्रतिशत का दर से व्याज भी सरकारी लेखे में जमा करना होगा। व्याज दोनों दिनों के लिए दिया जाएगा अर्थात् वह तिथि जिसका विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिसको सरकारी लेखे में रुपया निक्षेप किया जाता है। (इस दर में यदि कोई परिवर्तन किया गया तो तुरन्त उसकी सूचना दी जाएगी)। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमा-शुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है।

ये धनराशियां चानान के दाहिने ओर कोड सं० 5130000009 दर्शाते हुए या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए, या स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा या इसकी अनुषंगी संस्थाओं या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (आदेशित और आदाता) के नाम में और उसको देय दर्शनी हुण्डी के माध्यम से करनी चाहिए। इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं० 23-आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 24-10-68, सं० 132-आईटीसी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71, सं० 74 आईटीसी (पी एन)/74 दिनांक 31-5-1974 और सं० 103-आई टी सी (पी एन)/70, दिनांक 12-10-76 की शर्तों की ओर दिलाया जाता है। लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह "के डिपोजिट एण्ड एडवांसिज-843 सिविल डिपोजिट्स— डिपोजिट्स फार परचेजिस एटसेक्टा एग्राड-परचेजिस ग्रांड एंड फ्रम दि गवर्नमेंट आफ जापान फार 1982-83 (येन 1.948 बिलियन ग्रांट एंड डेबिट रिलीफ)"।

जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना सं० 132-आई टी सी (पी एन) 71, दिनांक 5-10-71 के अनुसार नकद जमा किया जाता है उनमें चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अग्रप्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी :—

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), पहली मंजिल, यू०सी०ग्रं० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

जिस मामले में तुल्य रुपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचना उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में व्याज की चुकाई गयी धनराशि और जिस अवधि के लिए व्याज की गणना की गई है और उसके साथ जमा किए गए तुल्य रुपय का पूरा व्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिए।

307 GI/84—2

समुद्र-पार संभरक के बैंकर के खर्चों सहित यदि कोई हो तो, बैंकिंग खर्च और बैंक आफ इंडिया, टोकियो, ब्रांच के अन्य खर्च इंडियन बैंक और बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जायेंगे।

4. भारतीय दूतावास, टोकियो

5. अवर सचिव (टी०ए) शाखा, वित्त मंत्रालय, (आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली।

भवदीय

लेखा अधिकारी,

MINISTRY OF COMMERCE

(Import Trade Control)

Public Notice No. 31—ITC(PN)84

New Delhi, the 6th June, 1984

Subject :—Licensing Conditions in respect of Public Sector Imports under the Japanese Grant Aid of Yen 1,948 Billion (Yen 1,948,670,000) (Debt Relief) for 1982-83 extended by the Government of Japan

F. No. IPC/23(2)/84.—The terms and conditions governing Public Sector Imports under the Japanese Grant Aid of Yen 1,948 Billion (Debt Relief) for 1982-83 extended by the Government of Japan as given in the Appendix to this Public Notice, are notified for information.

P. C. JAIN,

Chief Controller of Imports & Exports

APPENDIX TO MINISTRY OF COMMERCE
PUBLIC NOTICE NO. 31-ITC(PN)84 DATED
THE 6th JUNE, 1984

Licensing Conditions in respect of Public Sector Imports under the Japanese Grant Aid of Yen 1,948 Billion (Yen 1,948,670,000) (Debt Relief) for 1982-83 extended by the Government of Japan.

Section I—General Conditions

I (i) The Japanese Grant Aid of Yen 1,948 billion extended by the Government of Japan is untied in favour of OECD and developing countries except India. Accordingly the commodities and services incidental thereto to be procured under this Grant Aid can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be the eligible source countries under this Grant. The list of eligible commodities that can be imported under this Grant Aid is at Annexure-II.

I (ii) The licence will bear the superscription "Yen 1,948 billion Japanese Grant Aid for 1982-83". The licence code for the first and second suffix will be "SJN". These will also be repeated in the letter from the CCI&F forwarding the import licence.

I (iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank

charges which may be remitted through normal banking channels. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

I (iv) The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity of 12 months. For extension of the validity of the licence, the licensee should approach the licensing authority concerned who shall consult the Department of Economic Affairs (Japan Section) in the matter.

I (v) Firm order must be placed on C&F basis on the overseas suppliers located in Japan and in other eligible countries mentioned in Annexure-I and sent to the Under Secretary (TA), Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi (within 4 months from the date of issue of the import licence). "Firm Orders" means purchase orders placed by the Indian licensee on the Overseas supplier duly supported by order confirmation by the latter or purchase contract only signed by both the Indian importer and the Overseas supplier. Orders on Indian Agents of Overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I (vi) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section, within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para I(v) above cannot be placed within 4 months for valid reasons the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within 4 months. Such requests for extension in the ordering period will be considered etc. on the merit by the licensing authorities who may grant extension upto maximum period of 4 months. However, it will be payable on actual basis or whether the freight charges—further extension is sought beyond 4 months from the date of issue of this import licence, such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section) Ministry of Finance North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee.

In fixing the terminal date for shipment, it should be noted that this date should not be beyond 31-3-1985.

Section II—Special points to be kept in view while Negotiating a supply contract

II (i) (a) The C&F value of the contract should be expressed in Yen or US Dollar or Pound Sterling without fraction less than one Yen, one cent or one penny and should exclude Indian Agents commission, if any, which should be paid in Indian rupees. In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupee or in any other currency. The FOB cost and freight amount may be shown separately but it should be clarified in the contract whether

the freight charges indicated in the contract would be the amount payable irrespective of the actual charges.

(b) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese suppliers to the Bank of India, Tokyo.

(c) The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II (ii) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II (iii) Eligibility of Supplier.—The supplier shall be a national of the eligible source countries, or a juridical person registered and incorporated in the eligible source countries.

Section III

The following provision should be specifically incorporated in the supply contract :—

III (i) The contract is arranged in accordance with the agreement dated the 23-2-84 between the Governments of India and Japan concerning the Grant Aid—of Yen 1.948 billion for 1982-83 "and will be subject to the approval of Government of India".

III (ii) Payments to the overseas suppliers shall be made through an 'Authorisation to pay (A/P)' which will be issued by the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001, in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1982-83.

III (iii) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

III (iv) Where suppliers are located in Japan, they agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose they would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, at least six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importer require this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV Contract Approval by Govt. of India

IV (i) As soon as the orders are finalised, the licence should forward to the under Secretary (TA), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi, 4 copies of the contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian Importer placed on the Overseas supplier supported by order confirmation in writing by the overseas supplier or their photo copies complete in all respects with two photo copies of the relevant valid import licence and also two copies of the "Request for issue of A/P" in the form at Annex III. The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV (ii) If the contract documents "Request for issue of A/P" and other connected documents are found to be in order the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) will approve the contract and will arrange to send one set of the documents mentioned in (i) above each to the CAA&A, the Embassy of India, Tokyo and the Embassy of Japan in India.

IV (iii) On receipt of the documents mentioned at (ii) above the Controller of Aud. Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 will issue an 'Authorisation to pay (A/P) to the Bank of India, Tokyo' in the form at Annexure IV for making payment to the overseas supplier. Copies of the A/P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo the importer the importer's Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

IV (iv) On receipt of the Authorisation to pay (A/P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and the CAA&A.

IV (v) The foreign supplier shall, after effecting shipment, present through his banker the documents specified in the A/P to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the Supplier through his bankers.

IV (vi) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for advising the A/P and for arranging payment to the overseas supplier shall be settled by the concerned importer's Bank in India by remittances to the Bank of India, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's account.

Section V Responsibility for rupee deposit.

V (i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India Tokyo, to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised Banks as mentioned in (O) in Annexure-III who should release these negoti-

able set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen/US\$/Pound sterling payments made to the supplier alongwith interest charges thereon in cases where payable calculated at the rate of 12 per cent per annum for the first thirty days and at 18 per cent for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the foreign supplier to the date of actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 31—ITC(PN)/83 dated 10-8-83. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the supplier and also the day on which rupee deposits is made into Government account vide Public Notice No. 74—ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103—ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen/US\$/Pound payment will be prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8—ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. Any changes in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The licensee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before taking delivery of the documents from their bankers. It is the responsibility of the importer to ensure that the amounts due are correctly deposited in to the Government account promptly even when they obtain delivery of the goods from the customs authorities under exceptional circumstances. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K—Deposits and Advances 843-Civil. Deposits—Deposits for purchases etc. abroad-purchase Grant Aid from the Government of Japan" for 1982-83 (Yen 1.948 billion Grant Aid—Debt—Relief).

V (ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the challan or in the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if this is not possible it should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184—ITC(PN)/68 Dated 30-8-1968, No. 233—ITC(PN)/68 dated 24-10-68 and No. 132—ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74—ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103—ITC(PN)/76 dated 12-10-1976.

V (iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of Service charges within

seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the Importers, their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132—ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 and also in Public Notice No. 74—ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 read with Public Notice No. 103—ITC(PN)/76 dated 12-10-1976 is invariably entered in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :

- (a) Ministry of Finance 'A/P' (Authorisation to Pay) No. and date.
- (b) Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversation adopted.
- (c) Date of payment to the foreign supplier.
- (d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.
- (e) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government Account).

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A/P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note : Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

V (iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

SECTION VI—Miscellaneous provisions

VI (i) Reports on the utilisation of the import licence

The importer should send a monthly report, after the A/P has been issued regarding shipments and payments made thereagainst and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VI (ii) Notifying Suppliers of Special Conditions

The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VI (iii) Disputes

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-I under "Terms of payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the condition of contract.

VI (iv) Future Instructions

The Licensee shall promptly comply with directions, instructions or orders issued by the Govt. of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1982-83 from Japan.

VI (v) Breach or violation

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control Act).

VI (vi) List of Annexures

Annexure—I List of eligible source countries

Annexure—II List of eligible commodities

Annexure—III Form of Request for issue of Authorisation to Pay (A/P).

Annexure—IV Form of letter of Authorisation to Pay (A/P).

ANNEXURE—I

LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES

A. OECD Countries

Australia
Belgium
Canada
Denmark
Finland
France
The Federal Republic of Germany
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Japan
Luxembourg
the Netherlands
New Zealand
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
the United Kingdom and
the United States
Cameroon
Cape Verde Islands

Central African Rep.
Chad
Comoro Islands
Congo, People's
Republic of
Dahomay (1)
Equatorial Guinea
Ethiopia
Gambia
Ghana
Guinea
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Liberia
Malagasy Republic
Malawi
Mali
Mauritan-ia
Mauritius
Mozambique
Niger
Portuguese Guinea
Reunion
Rhodesia
Rwanda
St. Helena and dep (2)
Sao Tome and Principee
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Togo, Afars and (3)
Togo
Uganda
Un. Rep. of Tanzania
Upper Volta
Zaire Republic
Zambia

B. Developing Countries & Territories

(b1) Non-O.P.E.C. Developing Countries

I. Africa, North of Sahara
Egypt
Morocco
Tunisia

II AFRICA, South of Sahara
Angola
Botswana
Burundi

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.

(2) Including the following islands : Ascension, Tristan da. Inaccessibles, Nightingale, Gough.

(3) Main islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, St. Eustacit, St. Martin (Southern Part).

III. AMERICA, North and Cent.

Bahamas
Barbadoses
Belize
Bermuda
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
El Salvador
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Netherlands Antilles
Nicaragua
Panama
St. Pierre & Miquelon
Trinidad and Tabago
West Indies (Br.) n.i.c.

(a) Associated States (4)

(b) Dependencies (5)

IV. AMERICA, South

Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Falkland Islands
French Guiana
Guyana
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay

V. ASIA, Middle East

Bahrain
Israel
Jordan
Lebanon
Oman
Syrian Arab Republic
United Arab Emirates (6)
Yemen Arab Republic
Yemen, People's D. R. (7).

VI. ASIA, South

Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Burma

(4) Main islands :

St. Kitts (St. Christopher), Nevis-Anguilla, St. Lucia and Vincent.

(5) Main islands : Montserrat, Guyana, Turks and Caicos, and British Virgin Islands.

(6) Aiman, Dubai, Fajairah, Ras at Khaiman, Sharjah and Umm al Quaiwain.

(7) Including Aden and various sultanates and emirates.

Maldivis
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

ANNEXURE—II

ELIGIBLE COMMODITY LIST

VII. ASIA, Far East
Burma
Hong Kong
Khmer Republic
Korea, Republic of Laos
Macao
Malaysia
Phillippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Timer
Vietnam, Rep. of
Viet-Nam Dem. Rep.

VIII OCEANIA

Fiji
Gilbert & Ellice Is.
French Pelynesia (1)
Nauru
New Caledonia
New Hebrides (Br. and Fr.)
Rieu
Pacific Islands (US) (2)
Papua New Guinea
Solomon Islands (Br.)
Tongo
Wallis and Futuna
Western Samoa
Cock Islands

IX. EUROPE

Cyrus
Gibraltar
Greece
Malta
Spain
Turkey
Yugoslavia

(b2) Member or Associate Countries of OPEC

Algeria
Bolivia
Libyan Arab Republic
Gabon
Nigeria
Ecuador
Venezuela
Iran
Iraq
Kuwait
Qatar
Saudi Arabia
Abu Dhabi
Indonesia

(1) Comprising the Society Islands (including Tahiti), The Austral Islands, the Tuamotu Gambier Group and the Marquesas Islands.

(2) Trust Territory of the Pacific Islands, Caroline Islands Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam).

1. Rolls
2. Steel including special steel and alloy steel.
3. Components, attachments and spares for manufacture of trucks and tractors.
4. Chemicals.
5. Spares, components and raw materials for Japan aided Projects and Indo-Japanese Joint Ventures.
6. Components, attachments and spares for power tillers.
7. Machinery, components, attachments spares and raw materials.
8. Machinery and equipment for the Small Scale Sector.
9. Machinery, equipment and spares for the Oil & Natural Gas sector.
10. Fertilizer and such other items as may be mutually agreed upon.

ANNEXURE—III

"REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION TO PAY"

No.

To

The Controller of Aid Accounts and Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building 1st Floor,
Parliament Street,
New Delhi-110001.

Subject :—Import under the Japanese Debt-Relief Aid of Yen 1.948 billion for 1982-83.

Sir,

In connection with the import of _____ from Japan under the above mentioned Grant Aid, we furnish the following particulars to enable you to issue the A/P to the Bank of India, Tokyo in favour of the Supplier concerned :—

- (a) Name and Address of the Indian Importer.
- (b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.
- (c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.
- (d) Brief description of the goods.
- (e) Origin of the goods.

- (f) Gross C&F value of contract (in Yen).
- (g) Amount of Indian agents' commission (in Yen) if any, payable in Indian rupees.
- (h) Net C&F value (in Yen) for which the A/P is required.
- (i) Name and date of the contract with Suppliers.
- (j) Name and address of the Supplier.
- (k) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (l) Expected date of completion of deliveries.
- (m) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo, (indicating No. of sets of each and their disposal).
- (n) Shipment instructions (indicate if transshipment/partshipment permitted or not permitted).
- (o) Name and address of the Importer's Bank in India.
- (p) Whether a contract (s) under the same licence has been placed and if so, the No. date and value of such contract.

Yours faithfully,

ANNEXURE—IV

No.

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS**

New Delhi, the

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan)

Subject:—Import under Japanese Debt-Relief Grant Aid of Yen 1,948 billion. Issue of Authorisation to pay

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 13-3-1979 entered into with your Bank, you are hereby authorised to pay an amount not exceeding Yen ———— to M/S ———— (as per details given in the Appendix).

2. Please advise the Suppliers of the fact of receipt of this authorisation to Pay (A/P) and endorse a copy of this advice to the Government of Japan, Importers' Bank, Embassy of India, Tokyo and this Ministry.

3. Payments to the suppliers in terms of the A/P will be made on the basis of shipping documents etc. as indicated in the Appendix.

4. The banking charges including charges for handling documents payable to you by the importer will be settled by the Embassy of India Tokyo/Importers Bank.

5. As and when any payment is made by you on the basis of shipping documents etc. presented by the supplier, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry and the importer's bank.

6. No amendments to A/P may be issued in the absence of a specific authority from this Ministry.

7. The A/P will remain valid upto ————

Yours faithfully,
Accounts Officer

Copy forwarded to :—

1. Importer.....with reference to their letter No.....dated.....

2. Importer's Banker..... they are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen/\$/ Pound payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo, Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the overseas suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Overseas Suppliers in accordance with the Public Notice No. S-ITC (PN)/76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @ 12 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 18 per cent per annum for the period excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Govt. Account, is required to be deposited into the Government of India account in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-1976. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the overseas supplier and also the date on which rupee deposit is made into Government account. (Any change in this rate will be intimated if and when made). It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs Clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the challan or the S.B.I., Tis Hazari Delhi or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the S.B.I. or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the S.B.I., Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 23-ITC (PN)/68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31.5.74 and 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976.

The head of Account to be credited is "K—deposits & Advances—843—CIVIL deposit for purchases etc. abroad Purchases under Grant Aid from the Government of Japan" for 1982-83 (Yen 1,948 billion Grant Aid—Debt Relief).

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 should be sent by them to the address given below along with a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited along with the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

The banking charges, of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas suppliers bankers, if any, should be settled directly between the Indian Bank and the Bank of India, Tokyo Branch.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary (TA) Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

(Accounts Officer)